George Fernandes, somewhat amateurish. The only two ways by which you can avoid a nuclear attack are either by way of a nuclear weapons deterrent system, which we can do and which is very, very costly for a country like India, or, by way of nuclear diplomacy. I think, in this particular case, diplomacy is much less costly and much more productive, from a long-term point of view than deterrent itself. I think the other things, which you have mentioned are amateurish and do not really count for anything. It doesn't show any comprehension on the part of the Minister about the magnitude and scale of the problem involved in a nuclear confrontation.

MR. CHAIRMAN: It is only a suggestion. No answer is required.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I want to know ....

MR. CHAIRMAN: Question No. 306.

**306.[The questioner (Chaudhary Harmohan Singh Yadav) was absent. For answer, vide col. 31 infra]*

Lives lost due to rash and negligent Driving in Delhi

*307. SHRIMATI VEENA VERMA:†
SHRI AKHILESH DAS:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of human lives lost due to rash and negligent driving on roads in and round the National Capital Territory of Delhi, during 1997, 1998 and so far in 1999;

(b) the number of the accused brought to book and convicted during each year, and

(c) whether Government would bring modifications in the relevant laws to provide for adequate deterrence?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The number of persons killed in road accidents in the National Capital Territory of Delhi during the period in question is as follows:

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Veena Verma.

	1997	1998	1999 (upto 28.2.99)
No. of persons killed	2342	2123	319

(b) The number of persons who were arrested/convicted in accident cases registered during the period in question is as follows:

	1997	1998	1999 (upto 28.2.99)
No. of persons arrested	7642	6558	870
No. of persons convicted	277	73	01

In addition, the number of persons proceeded against under the Motor Vehicles Act, 1988 in order to instil discipline in the road users during last two years is as follows:

	1997	1998
Total challans	13,19,818	Rs 14,38,818
Total compounding fee	Rs. 14,93,92,000	. 16,81,04,050

(c) The proposal to amend the Motor Vehicles Act, 1988 so as to provide for stringent penalties for traffic related offences has been initiated.

श्री मती वीणा वर्मा : सर मैं मंत्री जी पूछना चाहती हूं कि बहुत लंबे समय से दुर्घटनाएं रेश ड्राइविंग की वजह से बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ गई है , एक तो बहुत लंबी योजना थी कि पुलिस कर्मियों में ज्यादा बल बढ़ाए जाएंगे और दूसरे यह जानना चाहती हूं कि एक्सीडेंड रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं । जिससे कि एक्सीडेंड हो ही नहीं ?

श्री सभापति : आप जब तक एक्सप्लेनेश करेंगे तब तक क्वेशचन आवार खत्म हो जाएगा ।

श्रीमती वीणा वर्मा : सभापति जी, मैं जानना चाहती हूं कि एक्सीडेटस न हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, इस समय कानून में जो रेश ड्राइविंग, नेगलिजेंस ड्राइविंग आदि के लिए दण्ड है, वह बहुत ही कम है । वह किसी प्रकार से डिटेंरेंट नहीं है । छोटा सा फाइन दंकर भी निकल सकता है । ला कमीशन ने पिछले दिनों रिकमेंडेशन की है, जो

बहुत गंभीर है रेश एण्ड नेगलीजेंस ड्राइविंग के लिए न केवल सजा बढ़ाई है । बल्कि यह भी व्यवस्था है कि जो इस प्रकार से रेश ड्राइविंग करने देगा, मालिक भी उसके लिए उत्तरदायी होगा और मुझे लगता है, कि इस मामले में हमने राज्य सरकारों से भी सलाह ली है , क्योंकि criminal laws is a Concurrent Subject उनकी सलाह लेकर हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

देश में हस्तशिल्पी

*306. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास हस्तशिल्पियों की संख्या के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वर्ष 1993 में, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसधांन परिषद (एन सीए ई आर) द्वारा की गई हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना में हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या 48.22 लाख होने का अनुमान लगाया गया है । इसके साथ-साथ राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1994-95 में हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या 48.22 लाख होने का अनुमान लगाया गया है । इसके साथ-साथ राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1994-95 में हस्तशिल्पियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया गया । आकंडे एकत्र करने सम्बंधी कार्य जम्मू एंव कश्मीर पंजाब व संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ को छोडकर सभी राज्यों में पूरा हो चुका है । इन राज्यों में आकडें एकत्र करने का कार्य चल रहा है ।

तीर्थ यात्रियों का शोषण

*308. **श्री नरेन्द्र मोहन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विविध स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है । और यहां तक कि अधिकांश तीर्थयात्रियों का अत्याधिक शोषण होता है,

(ख) सरकार द्वारा इन तीर्थयात्रियों को पेश आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई है तथा क्या इन योजनओं को लागू किया गया है,

(ग) क्या राज्य सरकारें इस दिशा में पर्याप्त सहयोग दे रही हैं, और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या है, जहां तीर्थयात्रियों की स्थिति दिन-प्रतिदिनऔर खराब हुई है अथवा किन राज्यों में विशेष सुधार किए जाने की आवश्यकता है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) इस आशय की कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है कि भारत में विभिन्न स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा उनमें से अधिकाशं का अत्याधिक शोषण किया जाता है । तथापि, कुछ बेईमान दुकानदारों, टैक्सी चालकों, इत्यदि द्वारा कभी-कभी तीर्थयात्रियों को परेशान करने की घटनाएं सूचित की जाती है ।

तीर्थस्थलों का विकास और उनका रख-रखाव करना, तीर्थयात्रियों को सूविधाएं उपलब्ध कराना, इत्यादि, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने कुछ चुने हुए तीर्थस्थलों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए एक योजना तैयार, की है । इस योजना के अधीन दी जाने वाली सुविधाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ , प्रसाधन पेयजल, खाने –पीने के सामान की दुकानें, रात्रि विश्राम स्थल, नहाने-धोने की सुविधाएं, इत्यादि शामिल है। इस योजना के अधीन, चुने हुए तीर्थस्थलों में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक की राशि के न्द्रीय राहत के रूप में दी जाती है, तथा शेष राशि को तीर्थस्थानों को शासित करने वाले निकायों द्वारा वहन किया जाता है । इस मामले में पर्यटन मंत्रालय को राज्य सरकारों की मदद मिल रही है ।

Indo-British defence ties

*309. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned, "Britain keen on defence ties", as reported in the Statesment dated the 21st January, 1999;

(b) if so, whether the British Government has shown interest to have defence ties with India; and

(c) if so, the details of discussions held in this regard during the past few months and the outcome thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) Yes, Sir.